

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

संशोधन प्रार्थना पत्र 57/2014/जयपुर

संशोधन प्रार्थना पत्र 58/2014/जयपुर

संशोधन प्रार्थना पत्र 59/2014/जयपुर

मैसर्स जैन इण्डस्ट्रीज

जयपुर

बनाम

सहायक आयुक्त,

प्रतिकरापवंचन, राज. वृत्त-तृतीय, जयपुर

एकलपीठ

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित

श्री ओ.पी.माहेश्वरी

सी.ए.

श्री ~~डी.पी.ओम्हा~~

उप राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांक 20.03.2017

अपीलार्थी

प्रत्यर्थी

अपीलार्थी की ओर से

प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय

ये तीनों संशोधन प्रार्थना पत्र राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 33 के अन्तर्गत अपीलार्थी की ओर से राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा अपील संख्या 176, 177 एवं 178/2012/जयपुर में पारित पृथक-पृथक निर्णय 13.05.2014 में संशोधन हेतु प्रस्तुत किये गये हैं।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान वृत्त-तृतीय, जयपुर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा 01.04.2006 से 30.06.2006 तक, 01.07.2006 से 30.09.2006 एवं 01.10.2006 से 31.12.2006 तक (वर्ष 2006-07) तक की अवधि के कर निर्धारण अधिनियम की धारा 25, 55 एवं 61 के अन्तर्गत पृथक-पृथक आदेश दिनांक 26.11.2006 को पारित किये गये। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त पारित किये गये आदेश के विरुद्ध उपायुक्त(अपील्स)तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर उन्होंने अपीलार्थी के अनुपस्थित रहने के कारण आदेश दिनांक 10.03.2010 पारित करते हुए अपीलें अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी में खारिज कर दी। आदेश दिनांक 10.03.2010 के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष उक्त अपीलों को रेस्टोर कराने हेतु रेस्टोरेशन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर उन्होंने रेस्टोरेशन आवेदन पत्रों को समुचित आधार के बिना पेश करने के कारण रेस्टोरेशन आवेदन पत्रों पेश किया जाना माना गया तथा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा जानबूझकर अनुपस्थित रहा इसलिए रेस्टोरेशन आवेदन पत्र खारिज करते हुए आदेश दिनांक 13.12.2011 पारित किया, जिसके विरुद्ध कर बोर्ड में अपीलें प्रस्तुत करने पर

कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा पृथक-पृथक निर्णय दिनांक 13.05.2014 पारित कर अपीलार्थी की अपीलें अस्वीकार कर दी, जिसमें संशोधन हेतु ये तीनों संशोधन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

अपीलार्थी की ओर से विद्वान सी.ए. ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी के अपीलार्थी के सी.ए. द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया था एवं स्थगन हेतु प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया, किन्तु उन पर विचार किये बिना रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया गया है, जो अविधिक है। उनका कथन है कि उनकी ओर से लिखित बहस में अनेक न्यायिक दृष्टान्तों का हवाला दिया गया था, जिस पर विचार करने के पश्चात गुणावगुण पर निर्णय पारित करना चाहिए था, जो नहीं किया गया है। उनका कथन है कि कर बोर्ड की माननीय एकलपीठ द्वारा प्रकरण के तथ्यों पर बिना कोई निष्कर्ष दिये अपीलें अस्वीकार की है, जो रिकार्ड से परिलक्षित भूल स्पष्टतः प्रकट होती है, इसलिए उन्हें संशोधित करते हुए उनकी ओर से प्रस्तुत तीनों संशोधन प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया।

विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि कर बोर्ड की माननीय एकलपीठ द्वारा अपील सुनवाई के समक्ष प्रस्तुत तर्कों एवं की गई बहस पर विचार करने के पश्चात चैतन्य मस्तिष्क से पृथक-पृथक निर्णय दिनांक 13.05.2014 पारित किये गये हैं। उनका कथन है कि व्यवहारी की ओर से संशोधन प्रार्थना पत्र पर जिस बिन्दु को उठाया गया है, उस पर बिन्दु को अपील सुनवाई के दौरान भी उठाया गया है, जिस पर विचार करने के पश्चात ही माननीय एकलपीठ द्वारा निर्णय दिनांक 13.05.2014 पारित किये हैं, इसलिए उक्त निर्णय संशोधन योग्य नहीं है। उनका कथन है कि अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत उन्हीं भूलों का सुधार किया जा सकता है जो बिना वाद-विवाद के रिकार्ड से परिलक्षित भूल (Apparent mistake on record) प्रकट होती है। निर्णय दिनांक 13.05.2014 में ऐसी कोई भूल नहीं बताई गई है, जो रिकार्ड से परिलक्षित होती हो, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मक्कड प्लास्टिक एजेन्सी (टैक्स अप डेट 29 पेज 253) को उद्धृत किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया एवं बहस के दौरान उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया। कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.05.2014 पर दृष्टिपात करने पर स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है कि अपीलार्थी द्वारा जिस तथ्य के आधार पर निर्णय

दिनांक 13.05.2014 में संशोधन हेतु निवेदन किया गया है, उसी बिन्दु को अपील की बहस के दौरान उठाया गया है, जिस पर विचार करने के पश्चात ही एकलपीठ द्वारा निर्णय पारित किया है।

बहस के दौरान विभागीय पक्ष की ओर से माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मक्कड प्लास्टिक एजेन्सी (टैक्स अप डेट 29 पेज 253) के प्रकरण में मत प्रतिपादित किया गया है कि चेतन मस्तिष्क के पारित किये गये निर्णय में संशोधन किया जाना उचित नहीं है, जिसका सारगर्भित अंश उद्धरित किया जाना समीचीन है :-

*"The scope and ambit of the power which could be exercised under section 37 of the Act of 1994 is circumscribed and restricted within the ambit of the power vested by the said Section. Such a power is neither a power of review nor is akin to the power of revision but is only a power to rectify a mistake apparent on the face of the record. Rectification implies the correction of an error or a removal of defects or imperfections. It implies an error, mistake or defect which after rectification is made right.*

*In the case of Commissioner of Income Tax, Bhopal v. Ralson Industries Ltd. reported in (2007) 2 SCC 326 a similar situation arose for the interpretation of this Court regarding the scope and ambit of Section 154 of the Income Tax Act vesting the power of rectification as against the power vested under Section 263 of the Income Tax Act, which is a power of revision. While examining the scope of the power of rectification under Section 154 as against the power of revision vested under Section 263 of the Income Tax Act, it was held by this Court as follows at Para 8:-*

*"8. The scope and ambit of a proceeding for rectification an order under section 154 and a proceeding for revision under Section 263 are distinct and different. Order of rectification can be passed in certain contingencies. It does not confer a power of review. If an order of assessment is rectified by the Assessing Officer in terms of Section 263 is exercised by a higher authority. It is a special provision. The revisional jurisdiction is vested in the Commissioner.*

*An order thereunder can be passed if it is found that the order of assessment is prejudicial to the Revenue. In such a proceeding, he may not only pass an appropriate order in exercise of the said jurisdiction but in order to enable him to do it, he may make such enquiry as he deems necessary in this behalf."*

*In paragraph 12 of the said judgment it was also held that when different jurisdictions are conferred upon different authorities, to be exercised on different conditions, both may not be held to be overlapping with each other. While examining the scope and limitations of jurisdiction under Section 154 of the Income Tax Act, it was held that such a power of rectification could only be exercised when there is an error apparent on the face of the record and that it does not confer any power of review. It was further held that an order of assessment may or may not be rectified and if an order of rectification is passed by the Assessing Authority, the rectified order shall be given effect to. We may also at this stage appropriately refer to yet another decision of this Court in Commissioner of Trade Tax, U.P v Upper Doab Sugar Mills Ltd. reported in (2000) 3 SCC 676, in which the power and scope of rectification was considered and pitted against the scope of review. The aforesaid decision was in the context of Section 39(2) of the U.P. Sales Tax(Amendment) Act, 1995 which provides the power of review. Section 22 of the said Act provides for rectification of mistake. In the said decision, it was held that when two specific and independent powers have been conferred upon the authorities, both powers can be exercised alternatively, but, it cannot be said that while exercising power of rectification, the authority can simultaneously exercise the power of review.*


*Both the aforesaid two decisions which were rendered while considering taxation laws are squarely applicable to the facts of the present case, it is also now an established proposition of law that review is a creature of the statute and such an order of a review could be passed only when an express power of review is provided in the statute. In the absence of any statutory provision for review, exercise of power of review under the garb of clarification/modification/correction is not permissible. In coming to the said conclusion we are fortified by the decision of this Court in Kalabharati Advertising V. Hemand Vimalnath Naruichania and Others reported in (2010) 9SCC 437. Section 37 of the Act of 1994 provides for a power to rectify any mistake apparent on the record. Such power is vested on the authority to rectify an obvious mistake which is apparent on the face of the records and for which a reappreciation of the entire records is neither possible nor called for. When the subsequent order dated 22-01-2009 passed by the Taxation Board is analysed and scrutinized it would be clear/apparent that the Taxation Board while passing that order*

*exceeded its jurisdiction by re-appreciating the evidence on record and holding that there was no mala fide intention on the part of assessee-respondent for tax evasion. Such re-appreciation of the evidence to come to a contrary finding was not available under Section 37 of the Act of 1994 while exercising the power of rectification of error apparent on the face of the records. Thus, the orders passed by the Taxation Board on 22-01-2009 as also impugned order and judgment passed by the High Court upholding the said order of the Taxation Board are hereby set aside and quashed and the original order passed by the Assessing Officer is restored.*

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त सिद्धान्त के आलोक में चैतन्य मस्तिष्क से पारित किये गये आदेश को इस स्तर पर विधिक रूप से संशोधित नहीं किया जा सकता है।

उपरोक्त विवेचित तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत किये गये संशोधन प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

  
(मदन लाल मालवीय)  
सदस्य